



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature
28/9/97

सं० 180]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1997/भाद्र 26, 1919

No. 180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1997/BHADRA 26, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1997

विषय : कोरिया गणराज्य, ताइवान, जापान तथा मलेशिया से पोलिस्ट्रीन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 7/1/97-एड्डीडी.—मैसर्स पोलिस्ट्रीन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा जाएगा) के पास घरेलू उद्योग की ओर से एक याचिका दायर की है जिसमें कोरिया गणराज्य, मलेशिया, जापान और ताइवान से पोलिस्ट्रीन के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

1. स्थिति : याचिकाकर्ता भारत में पोलिस्ट्रीन उत्पादकों की एक संस्था है और याचिका को भारत में पोलिस्ट्रीन के निम्नलिखित तीन उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है।

*सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स लि.

*मैकडोवेल लि. (हिन्दुस्तान पोलिमर्स लि.)

*राजस्थान पोलिमर्स एंड रेजिन्स लि.

भारत में पोलिस्ट्रीन के उत्पादन का अधिकांश भाग उपर्युक्त तीनों कम्पनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः यह संस्था घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की शर्तों को पूरा करती है।

2. संबंधित उत्पाद : मौजूदा जांच में संबंधित उत्पाद कोरिया गणराज्य, मलेशिया, जापान तथा ताइवान मूल का या वहां से निर्यातित पोलिस्ट्रीन है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क शीर्ष 3903 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और मौजूदा जांच के लिए किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3. संबंधित देश/राज्य क्षेत्र : मौजूदा जांच में कोरिया गणराज्य, ताइवान, मलेशिया, जापान तथा मलेशिया शामिल हैं।

4. **समान वस्तुएं** : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कोरिया गणराज्य, मलेशिया, जापान तथा ताइवान से निर्यातित वस्तुएं तथा याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुएं आपस में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं। अतः इनकी विशेषताएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। अतः संबंधित कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नियमों के अंतर्गत कोरिया गणराज्य, मलेशिया, जापान तथा ताइवान से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा सकता है।

5. **डम्पिंग तथा डम्पिंग मार्जिन**

- (क) **सामान्य मूल्य** : याचिकाकर्ता ने आरोपित देशों के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। सामान्य मूल्य का यह दावा कोरिया आर. पी. में एक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत सूचियों (कोरिया आर. पी. के मामले में), जापान में एक विनिर्माता द्वारा रिपोर्ट की गई कीमतों (जापान के मामले में) सिंगापुर में एक कम्पनी द्वारा रिपोर्ट की गई कीमतों (मलेशिया के मामले में) तथा सूची की कीमतों जिसमें छूट शामिल नहीं (ताइवान के मामले में) पर आधारित हैं।
- (ख) **निर्यात कीमत** : याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एस.) कलकत्ता, के आंकड़ों तथा 1995-96 एवं 1996-97 के लिए मुंबई और कलकत्ता बंदरगाह के सीमाशुल्क दैनिक सूचियों से संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है।
- (ग) जिस मूल्य पर आरोपित देशों से वस्तुओं का निर्यात किया गया है, आरोपित देशों में इसके सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त प्रथम-दृष्ट्या प्रमाण हैं तथा यह भी कि आरोपित देशों में पोलिस्टिरीन का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी ज्यादा है जिस मूल्य पर भारत में इनका निर्यात किया गया है, जिससे प्रथम-दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा आरोपित देशों से वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में पोलिस्टिरीन के आयातों से युक्त कम्पनियों को वास्तविक हानि हुई है और आगे भी वास्तविक हानि की आशंका है। पोलिस्टिरीन के आयात भारत से ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिससे कि भारत में पोलिस्टिरीन की घरेलू कीमतों पर मन्द करने वाले तथा/या रोकने वाले प्रभाव पड़े। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापक जैसे कि उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक हानि हुई है और उससे वास्तविक हानि की आशंका भी है। याचिकाकर्ता ने अपना यह दावा सिद्ध करने के लिए कि आरोपित देशों से आयातों के कारण इसे वास्तविक क्षति हुई है, संबंधित कम्पनियों द्वारा उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर की गई बिक्री (प्रशासनिक, सामान्य और बिजनेस खर्च सहित) एवं उचित प्राप्ति विश्वास किया है जिससे कि सभी तीनों कम्पनियों को वित्तीय हानि हुई है।

दृष्ट्या इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आरोपित देशों से पोलिस्टिरीन के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

7. **पाटन जांच की शुरुआत** : अतः प्राधिकारी, कोरिया गणराज्य, जापान, मलेशिया तथा ताइवान मूल के या वहां से निर्यातित सामान के आर. पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव की प्रतिपाटन जांच शुरू करते हैं।
8. **अवधि** : वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च 1997 तक की है।
9. **सूचना प्रस्तुतिकरण** : संबद्ध माने जाने वाले उक्त देशों के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र निर्धारित विधि से सुसंगत सूचना तथा अपने विचार श्री दीपक चटर्जी निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को प्रस्तुत कर दें। कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित विधि पूर्वक जांच से अपनी सूचना भेज सकती है।
10. **समय-सीमा** : जान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिनों के भीतर पहुंच जाए। परन्तु ज्ञात निर्यातकों और आयातकों, जिन्हें अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं, को उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर यह सूचना भेजी जानी आवश्यक है।
11. **सार्वजनिक मिसिल की निरीक्षण** : नियम 6(7) की शर्तों के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी सार्वजनिक मिसिल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतरण होते हैं।
12. यदि कोई पार्टी पहुंचने से मना होती है अथवा अन्यथा वह उपयुक्त अवधि में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करवाती है अथवा सूचना में सांकेतिक रूप से अड़थक डालती है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है।

दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 1997

Subject : Initiation of anti dumping investigation concerning import of Polystyrene from Korea RP, Taiwan, Japan and Malaysia

No. 7/1/97-ADD.—M/s Polystyrene Producers Association filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Polystyrene from Korea RP, Malaysia, Japan and Taiwan and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties.

1. **Standing:** The petitioner is an association of Polystyrene producers in India and the petition is supported by the following three producers of Polystyrene in India:

- ♦ Supreme Petrochem Ltd.;
- ♦ McDowell & Co. Ltd., (Hindustan Polymers Ltd.);
- ♦ Rajasthan Polymers and Resins Ltd.

Production of the above three companies constitutes majority production of polystyrene in India and the association, therefore, satisfies the standing to file the petition, on behalf of the domestic industry.

2. **Product Involved:** The product involved in the present investigation is Polystyrene originating in or exported from Korea RP, Malaysia, Japan and Taiwan, classified under custom sub-heading 3903 of the Customs Tariff Act. The classification is, however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
3. **Countries/Territories Involved :** The countries/territories involved in the present investigations are the Republic of Korea, Taiwan, Japan and Malaysia.
4. **Like Goods:** The petitioner has claimed that the goods exported from Korea RP, Malaysia, Japan and Taiwan and being produced by the petitioner are being consumed interchangeably and therefore have characteristics closely resembling each other. Goods produced by the

subject companies can, therefore, be treated as like articles to the goods imported from Korea RP, Malaysia, Japan and Taiwan within the meaning of the Rules.

5. Dumping and Dumping Margin:

- a. Normal value: The petitioner has claimed normal value based on the prices prevailing in the domestic market in the subject countries/territories. The claim of normal value is based on the price lists of a producer in Korea RP (in case of Korea RP), prices reported by a manufacturer in Japan (in case of Japan), average prices reported by a company in Singapore (in case of Malaysia) and list prices, net of discounts (in case of Taiwan).
 - b. Export price: The petitioner has claimed export price on the basis of data from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCIS), Calcutta and the data compiled from the Customs Daily lists for the Mumbai and Calcutta ports for 1995-96 and 1996-97.
 - c. There is sufficient prima facie evidence with regard to the normal values in the subject countries/territory, the prices at which goods have been exported from the subject countries/territory and that the normal values of Polystyrene in the subject countries/territory are significantly higher than the price at which these have been exported to India, indicating, prima facie, that the goods are being dumped by the exporters from the subject countries/territory.
6. Injury: The petitioner has claimed that imports of Polystyrene in India have caused the subject companies material injury and further threatens material injury. The imports of Polystyrene are entering in India at such a price as to have a significant depressing and/or suppressing effect on the domestic prices of Polystyrene in India. The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. also collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered material injury and the same also pose a threat of material injury. The petitioner has relied upon sales by the subject companies at prices significantly below the cost of production (including administrative, general and selling expenses) and fair return resulting in significant financial losses to all the three companies to establish its claim that material injury has been caused to it by the imports from the subject countries/territory.

There is sufficient prima facie evidence that the imports of polystyrene from the subject countries/territory have caused material injury to the domestic industry.

7. Initiation of Anti-Dumping Investigation: The Authority, therefore, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged

dumping of the subject goods originating in or exported from Korea RP, Japan, Malaysia and Taiwan.

8. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of present investigations is 1st April, 1996 to 31st March, 1997.
9. Submission of Information: The exporters in the said countries/territory and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to Shri Dipak Chatterjee, Designated Authority, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
10. Time Limit: Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
11. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority

2327-41/97-2

